

केरल में अवसंरचना को प्रोत्साहन

प्रलिस के लिये:

[राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन \(NIP\)](#), [प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना](#), विश्व बैंक द्वारा भारत की शहरी अवसंरचना आवश्यकताओं का वित्तपोषण, [राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक \(NBFID\)](#), [वकिसति भारत](#), [अमृत काल](#), [मेक इन इंडिया](#)

मेन्स के लिये:

भारत का बुनियादी ढाँचा क्षेत्र- महत्त्व, चुनौतियाँ और संबंधित पहल

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [प्रधानमंत्री \(Prime Minister- PM\)](#) ने कोच्चि, केरल में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें [कोचीन शिपियार्ड लिमिटेड \(CSL\)](#) में [न्यू ड्राई डॉक \(NDD\)](#), [CSL](#) की अंतरराष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुविधा ([International Ship Repair Facility- ISRF](#)) एवं [इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड \(IOCL\)](#) का [LPG](#) आयात टर्मिनल शामिल हैं।

- ये प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएँ भारत के बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने तथा इसमें क्षमता सृजन एवं आत्मनिर्भरता के लिये प्रधानमंत्री के वज़िन के अनुरूप हैं।

केरल में उद्घाटन की गई तीन वभिन्न परियोजनाएँ क्या हैं?

- न्यू ड्राई डॉक:**
 - 310 मीटर की लंबाई के साथ न्यू ड्राई डॉक (NDD) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
 - यह राष्ट्रीय गौरव इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो [INS](#) विक्रान्त अथवा अन्य बड़े जहाज़ों के वसि्थापन से दोगुने वमिान वाहक को संभालने में सक्षम है।
 - भारत के इंजीनियरिंग कौशल और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाने वाली एक प्रमुख परियोजना [NDD](#) इस क्षेत्र के सबसे बड़े समुद्री अवसंरचना में से एक है।
 - इसमें दक्षता, सुरक्षा और पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिये नवीनतम तकनीक तथा नवाचारों को शामिल किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुविधा:**
 - अंतरराष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुविधा (ISRF) भारत का पहला पूर्ण रूप से वकिसति शुद्ध जहाज़ मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र है जो जहाज़ मरम्मत उद्योग की क्षमता में 25% की वृद्धि करेगा।
 - ₹970 करोड़ के निवेश पर निर्मित यह आपातकालीन स्थिति के दौरान भारत के नौसेना और तटरक्षक जहाज़ों के लिये त्वरित टर्नअराउंड (जहाज़ पर से माल उतारने व लादने की क्रिया) प्रदान करेगा।
 - ISRF, CSL की वर्तमान जहाज़ मरम्मत क्षमताओं का आधुनिकीकरण तथा वसितार करेगा एवं इसे एक वैश्विक जहाज़ मरम्मत केंद्र के रूप में परिवर्तित करेगा।
- IOCL के लिये LPG आयात टर्मिनल:**
 - IOCL के लिये एक LPG आयात टर्मिनल का भी कोच्चि में उद्घाटन किया गया, जिसमें 3.5 कर्मी. लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के माध्यम से मल्टी-यूज़र लक्विडि टर्मिनल जेट्टी से जुड़े अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ काम किया गया है।
 - टर्मिनल का लक्ष्य 1.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) का कारोबार प्राप्त करना है। यह सड़क व पाइपलाइन हस्तांतरण के माध्यम से LPG वितरण सुनिश्चित करेगा, जिससे केरल और तमलिनाडु में बॉटलिंग संयंत्रों को प्रत्यक्ष लाभ होगा।
 - यह LPG की नरितर आपूर्ति सुनिश्चित करके भारत के ऊर्जा अवसंरचना को भी महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे क्षेत्र और उसके आसपास के लाखों परिवारों एवं व्यवसायों को लाभ होगा।
 - यह परियोजना सभी के लिये सुलभ और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने की दशा में भारत के प्रयासों को और मज़बूत करेगी।

इन परियोजनाओं का महत्त्व क्या है?

- **समुद्री विकास हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण:**
 - प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास' दृष्टिकोण से जुड़ी परियोजनाओं द्वारा स्थापित वैश्विक बेंचमार्क पर जोर दिया।
 - **मैरीटाइम अमृत काल वजिन- 2047** कोचि को एक प्रमुख **समुद्री क्लस्टर और ग्रीन शिप हेतु एक वैश्विक केंद्र** के रूप में विकसित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जो उत्कृष्टता एवं नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **समुद्री क्षेत्र में नविश और रोजगार:**
 - इस पहल का लक्ष्य 45,000 करोड़ रुपए का महत्त्वपूर्ण नविश प्राप्त कर समुद्री क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोगों के लिये रोजगार सृजन करना है।
 - ये प्रयास भारत के टन भार को बढ़ाने, **आत्मनिर्भर** बनने और वदेशी जहाजों पर भारत की निर्भरता को कम करने पर केंद्रित हैं।
- **कोचीन शिपयार्ड लमिटिड (CSL) की भूमिका:**
 - CSL, जैसे नॉर्वे में **स्वायत्त इलेक्ट्रिक नौकाएँ/जहाज (Barges) उपलब्ध कराने** के लिये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, एक प्रमुख समुद्री/मैरीटाइम अग्रणी के रूप में भारत के पुनरुत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
 - **अगली पीढ़ी के हरित प्रौद्योगिकी (Next-Generation Green Technology) जहाजों** सहित शिपयार्ड का प्रभावशाली उत्पाद पोर्टफोलियो इसे भारत के समुद्री उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय गौरव और पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - कोचि में राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक परियोजनाएँ भारत की अभियांत्रिकी शक्त को प्रदर्शित करती हैं। इनसे पर्यावरणीय दायित्व पर जोर देते हुए महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक बचत और CO2 उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद की जाती है।
- **वैश्विक दृष्टि के साथ संरक्षण:**
 - **मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (MEEEC) के संबंध में भारत की G20 अध्यक्षता** के दौरान किये गए समझौतों पर प्रकाश डालते हुए, PM ने रेखांकित किया कि MEEEC भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर विकसित भारत के निर्माण को और भी मजबूत करेगा।
- **समुद्री बुनियादी ढाँचे के लिये भविष्य की योजनाएँ:**
 - बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इन परियोजनाओं के आधार पर भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें शामिल हैं:
 - **जहाज निर्माण एवं मरम्मत में उत्कृष्टता केंद्र** की स्थापना।
 - **रणनीतिक स्थानों पर जहाज मरम्मत समूहों** का निर्माण।
 - जहाज मरम्मत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये व्यापार शर्तों में छूट।
 - वाडनार में जहाज मरम्मत सुविधा के लिये चर्चा चल रही है।

प्रमुख एवं छोटे बंदरगाह:

- **भारत के प्रमुख बंदरगाह:**
 - देश में **12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह (छोटे बंदरगाह)** हैं।
 - प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजर (पहले एन्नोर), वी. ओ. चिदिबरनार, वशिखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।
- **प्रमुख बंदरगाह बनाम छोटे बंदरगाह:**
 - भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रमुख एवं छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - सभी **12 बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत शासित हैं और केंद्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में हैं।**
 - सभी छोटे बंदरगाह, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत शासित हैं और राज्य सरकारों के स्वामित्व तथा प्रबंधन में हैं।
- **हाल में हुए विकास:**
 - भारतीय बंदरगाहों ने **पछिले 10 वर्षों में दोहरे अंक की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।**
 - जब बदलाव के समय की बात आती है तो भारत कई विकसित देशों से आगे निकल गया है।
 - भारतीय नाविकों से संबंधित कानूनों में समय पर बदलाव से उनकी संख्या में **140% की वृद्धि हुई है।**

Roadblocks in key sectors

A

HIGHWAYS

- Delays in land acquisition; lenders stop lending midway
- Tendering of projects to low-traffic entity
- Unclear exit policy for road developer; NHA is a developer as well as the regulator which causes a conflict of interest in case of arbitration so there is a need for a clear distinction of roles for NHA

PORTS

- Multiple changes in tariffs setup by the Tariff Authority for Major Ports make it difficult to evaluate the cost of projects
- Delays in tariff fixation

AIRPORTS

- Lack of consistency in tariff methodology and concession tariff framework
- Switching from single till tariff method to hybrid till creates difficulty in assessing the cost of projects
- Delays in the passage of tariff orders cause problems in the timely execution of projects

WIND

- Inconsistent policy at Central and State govt level
- Accelerated depreciation leads to non-viability
- State regulators do not honour renewable purchase obligation

TELECOM

- Lack of predictability
- Inconsistent policy and regulatory framework; govt refuses to honour PPAs signed earlier
- Aggressive bidding to some extent

POWER

- Coal block deallocation causing execution delays and losses to project developers
- New auction-based coal linkage approved by government in 2017, uncertainty remains regarding the validity of old contracts
- Inconsistency in the interpretation of PPA
- Inconsistency in Central & State regulation, for instance, the Central electricity Act allows open access, but State governments do not adhere to it causing the problem in execution
- Unstable financial health of State utility causes a delay in the payment cycle

GREENFIELD PROJECTS

- Land acquisition delay
- Nature of developers have been contractors which leads to low-cost bidding making the project unviable
- Bank loans are given out for **10/15/18 years** but the interest reset clause poses a high risk on overall investment return evaluation, sometimes **8%** interest rates are increased up to **14-15%** rendering the project unviable

BROWNFIELD PROJECTS

- Government questions the validity of existing projects (eg, with rates of solar energy slashing, will the contracts entered on higher tariffs remain valid or not?)
- There is a strong need for the ability to have more credible infrastructure developers and partners

UNIFIED LOGISTICS INTERFACE PLATFORM (ULIP) IS DESIGNED TO ENHANCE EFFICIENCY AND REDUCE THE COST OF LOGISTICS BY CREATING A TRANSPARENT, ONE-WINDOW PLATFORM

बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को मज़बूत करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- नीति/नियामक ढाँचे में नरिंतरता सुनिश्चित करना:**
 - नविदिा प्रक्रिया में एक बेहतर नियामक वातावरण और नरिंतरता की आवश्यकता है। वभिन्नि सरकारी वभिगों में नरिंतरता और नीतगित सामंजस्य की कमी को प्राथमकिता से संबोधति कया जाना चाहयि।
 - तनावगरसत परसिपत्तयिों की समस्य़ा से नपिटने के लयि सरकार और RBI के मध्य एक समग्र दृष्टकिण होना चाहयि।
 - गैर-नषिपादति संपत्तयिों, PSUs के पुनरुद्धार के लयि सभी कषेत्रों में एक समरपति नीतिका नरिमाण करने की आवश्यकता है।
- उचति उपयोगकर्त्ता शुल्क:**
 - यह अवसंरचना वतितपोषण, अवसंरचना सेवा प्रदाताओं की वतितयि व्यवहार्यता और पर्यावरण एवं संसाधन उपयोग संवहनीयता को बढाने के लयि यह आवश्यक है।
 - उपयोगकर्त्ता शुल्क महत्त्वपूरण हैं कयोंकि देश भर के कई कषेत्रों में आंशकि रूप सेशून्य या बहुत कम उपयोगकर्त्ता शुल्क के कारण कीमती संसाधनों (जैसे- भूजल) का अत्यधकि उपयोग एवं अपव्यय होता है।
 - उचति उपयोगकर्त्ता मूल्यों से प्रेरति पर्यावरणीय संवहनीयता एवं संसाधन उपयोगदक्षता के अलावा इस नीतिप्राथमकिता में अपार संसाधन सृजन क्षमता भी है।
- स्वायत्त अवसंरचना के वनियमन:**
 - जैसे-जैसे भारत और वशि्व नजिी भागीदारी के लयि अधकि कषेत्रों को खोलेंगे, नजिी कषेत्र अनवार्य रूप से स्वायत्त अवसंरचना के वनियमन की मांग करेगा।
 - वशि्व में रुझान बहु-कषेत्रीय नयामकों की ओर है कयोंकि बुनियादी ढाँचा कषेत्रों में नयामक भूमकि आम है और ऐसे संस्थान नयामक कषमता का नरिमाण करते हैं, संसाधनों का संरक्षण करते हैं तथा नयामक कब्जे को रोकते हैं।

■ परसिंपत्तपुनरचकरण (AR) और BAM:

- ब्राउनफील्ड परसिंपत्तपुनरचकरण (Brownfield Asset Monetisation - BAM) का मूल वचिर जोखमि रहति ब्राउनफील्ड सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में बँधे धन को मुक्त करके त्वरति ग्रीनफील्ड नविश के लिये ब्राउनफील्ड AR के माध्यम से अवसंरचना के संसाधनों को बढ़ाना है।
- इन परसिंपत्तियों को एक टरसट {इनफ्रासटरकचर इन्वेसटमेंट टरसट (InvIT)} या एक कॉर्पोरेट संरचना (टोल ऑपरेट ट्रांसफर (TOT) मॉडल) में स्थानांतरति कथि जा सकता है, जो पूंजीगत वचिर के बदले में संस्थागत नविशकों का नविश प्राप्त करता है (जो इन अंतरनहिति परसिंपत्तियों से भवषिय के नकदी प्रवाह के मूल्य को प्राप्त करता है)।

- भारत के पास बुनयिदी ढाँचा क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड परसिंपत्तियों का एक बड़ा भंडार है।

■ घरेलू नधियों का उपयोग:

- भारतीय पेंशन फंड जैसे घरेलू स्रोत, जो नषिकरयि पड़े हैं, यदकिशलतापूर्वक उपयोग कथि जाए तो इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मलि सकता है।
- भारत अवसंरचना के वकिस को बढ़ावा देने के लिये घरेलू धन के कुशल उपयोग पर कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।

अवसंरचना से संबंधति वभिन्नि सरकारी पहल क्य़ा हैं?

- प्रधानमंत्री गतशिकतयोजना
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
- शहरी अवसंरचना वकिस नधि
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिकस नीति
- डेडकिटेड फरेट कॉरडोर
- सागरमाला परयोजना

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न1. 'राष्ट्रीय नविश और बुनयिदी अवसंरचना कोष' के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2017)

1. यह नीतआयोग का एक अंग है।
2. वर्तमान में इसके पास 4,00,000 करोड़ का कोष है।

नीचे दथि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

प्रश्न 2. भारत में "सार्वजनिक रूप से महत्त्वपूर्ण बुनयिदी अवसंरचना" शब्द का प्रयोग कसिके संदर्भ में कथि जाता है (वर्ष 2020)

- (A) डिजिटल सुरक्षा बुनयिदी अवसंरचना
(B) खाद्य सुरक्षा बुनयिदी अवसंरचना
(C) स्वास्थ्य देखभाल और शकिस हेतु बुनयिदी अवसंरचना
(D) दूरसंचार और परविहन बुनयिदी अवसंरचना

उत्तर: (A)

??????:

प्रश्न. "अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक वकिस के लिये बुनयिदी अवसंरचना में नविश आवश्यक है।" भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजयि। (वर्ष 2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/infrastructure-push-in-kerala>

